राष्ट्रीय संस्करण

शेफाली की शानदार बल्लेबाजी से भारत सेमीफाइनल में

>>14

वर्ष 3 अंक 262

दैनिक जागरण

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 28 फरवरी 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

सरोकार

इन्हें 'अफसर जीजी' कहतीं हैं आदिवासी महिलाएं

उदयपुर : राजस्थान के उदयपुर संभाग में पदस्थ दो महिला आइएएस अधिकारी जिनकी शैक्षिक योग्यता स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में है, किस तरह पिछड़े आदिवासी इलाके में प्रशासनिक दायित्व के साथ ही महिलाओं के कल्याण के लिए प्रयास कर रही हैं, लाइव रिपोर्ट। (पेज-10)

जागरण विशेष

निमाड़ में लाल मिर्च ने किया कमाल, हर जेब मालामाल

इंदौर : मध्य प्रदेश के निमाड़ की मिर्च ने फिर मंडियों में रौनक भर दी है।हजारों किसानों के साथ ही व्यापारियों और निर्यातकों तक के चेहरे खिल उठे हैं। मिर्च के अर्थतंत्र से उत्साहित सरकार 29 फरवरी से यहां दो दिवसीय मिर्च महोत्सव मनाने जा रही है। (पेज-10)

विश्वास.News

पुरानी तस्वीर दिल्ली हिंसा से जोड़कर वायरल ?

विश्वास न्यूज की पड़ताल • पेज 5

आप पार्षद पर हत्या का केस, घर से मिला तबाही का सामान

दंगे का दाग ▸ आम आदमी पार्टी ने पार्षद को निकाला, हिंसा में मृतकों की संख्या हुई 38, नाले से मिले दो शव

पार्षद ताहिर हुसैन के घर से पेट्रोल बम, तेजाब के पाउच व बोतलें बरामद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

ताहिर हुसैन। फाइल

- पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया, घरों की ली जा रही तलाशी
- केजरीवाल ने मृतकों के आश्रितों को दस-दस लाख देने की घोषणा की

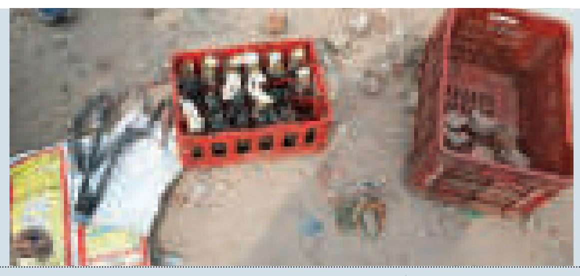

नई दिल्ली के खजूरी के ई ब्लॉक स्थित आप पार्षद ताहिर हुसैन की छत पर पेट्रोल बम, गुलेल व पत्थर। जागरण

दिल्ली में फैली सांप्रदायिक हिंसा के दौरान आइबी (इंटेलीजेंस ब्यूरो) के कांस्टेबल अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन सबके बीच दिल्ली पुलिस ने हिंसा की जांच के लिए दो एसआइटी गठित की है। अब तक 48 मामले दर्ज किए गए हैं और 130 को गिरफ्तार किया है। वहीं, आप ने ताहिर को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है।

इससे पूर्व गुरुवार को दिन में पार्षद के घर की छत से पेट्रोल बम, तेजाब के पाउच, गुलेल के साथ काफी संख्या में तेजाब की बोतलें भी बरामद हुई हैं। पुलिस ने इस घर को सील कर दूसरे घरों की तलाशी शुरू कर दी है। इस बीच, विभिन्न अस्पतालों में भर्ती नौ और लोगों के दम तोड़ने और नाले से दो शव मिलने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। घायलों की संख्या 400 से ज्यादा है। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मृतकों के आश्रितों को दस-दस लाख रुपये और घायलों को दो-दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का एलान किया है।

पार्षद के घर में हुई अंकित की हत्या : बुधवार को आइबी जवान अंकित शर्मा का शव बरामद हुआ था। स्वजनों का आरोप है कि हिंसा रोकने गए अंकित को पार्षद ताहिर हुसैन के समर्थकों ने घेर लिया और पार्षद के घर में ले जाकर हत्या कर दी। गुरुवार को भी गोकलपुरी में नाले से दो शव बरामद किए गए। शिव विहार में दंगाइयों ने एक दुकान को आग लगाने के साथ चार लोगों को जख्मी कर दिया। एक युवक गोली लगने से जख्मी हुआ। नूर-ए-इलाही, ब्रह्मपुरी रोड, बृजपुरी, चमन पार्क और शिव विहार तिराहे पर हालात तनाव भरे ही दिखे। अन्य इलाकों में शांति रही और जनजीवन पटरी पर लौटता हुआ भी नजर आया। दस से ज्यादा लोग अभी लापता है। इनके स्वजन अस्पतालों में भटक रहे हैं।

मुश्किल से हुई पड़ोसी की शादी : पार्षद ताहिर के घर से बरामद सामान से पता चलता है कि उसने दंगे से पहले ही घर में इन्हें इकट्ठा कर लिया था। इसके ठीक बराबर वाले घर में शादी के खानपान की तैयारी चल रही थी, जिसे दंगाइयों ने तबाह कर दिया है। वहां पार्क की गई कारें जला दीं। बड़ी मुश्किल से परिवार वालों ने लड़की की विदाई की। उनका आरोप है कि ताहिर के घर से ही दंगाई आए थे।

कई इलाके तबाह : करावल नगर रोड, शिव विहार, ब्रजपुरी, नूर-ए-इलाही रोड यमुना विहार, मौजपुर रोड, ब्रह्मपुरी रोड में सर्वाधिक बर्बादी हुई है। सबसे ज्यादा मौतें शिव विहार, करावल नगर, मौजपुर और जाफराबाद में हुईं। इन इलाकों में सड़कों पर ईंट-पत्थरों के टुकड़े भरे पड़े हैं। पुलिस ने घरों की तलाशी शुरू की तो छतों पर बड़ी गुलेल, भारी मात्रा में ईंट-पत्थर और एसिड की भरी बोतलें मिली हैं।

दंगे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, भाजपा का पलटवार पेज>>5

हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में अघोषित कर्फ्यू

हिंसाग्रस्त इलाकों में पुलिस की ओर से अघोषित कर्फ्यू है। गुरुवार सुबह इसमें थोड़ी छूट दी गई। लोगों ने घरों से बाहर निकलकर जरूरी सामान खरीदा। हालांकि आधिकारिक रूप से कर्फ्यू हटाए जाने का अभी एलान नहीं हुआ है। दंगे के दौरान अपने घरों को छोड़कर दूसरे इलाकों में जाने वाले लोग अब लौटने लगे हैं।

शांति को बहाल करने में जुटी पुलिस

शांति बहाली के लिए विशेष पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) एसएन श्रीवास्तव व अन्य संयुक्त आयुक्त लगातार गश्त कर रहे हैं। दोनों समुदायों के प्रमुख लोगों के साथ पुलिस अधिकारी बैठकें कर शांति मार्च निकाल रहे हैं। धार्मिक स्थलों से शांति बनाए रखने का एलान कराया जा रहा है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दंगा प्रभावित इलाकों में लंगर वितरित किया।

फिर टालीं बोर्ड परीक्षाएं

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए एक सप्ताह के अंदर तीसरी बार दिल्ली के उत्तर-पूर्वी व पूर्वी जिले में 28 व 29 फरवरी को होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला लिया है।

केजरीवाल बोले, आप का कोई दोषी हो तो दें दोगुनी सजा

अरविंद केजरीवाल प्रेट्र

आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन पर दंगा भड़काने के आरोपों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दंगे में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर दंगे में आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे दोगुनी सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।

कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं : संघ

नागपुर, प्रेट्र : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह सुरेश भय्याजी जोशी ने गुरुवार को दिल्ली में हुए दंगों पर कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार को दिल्ली में शांति बहाल करनी चाहिए, जहां सांप्रदायिक हिंसा ने सब तहस-नहस कर दिया है। संघ के नेता सुरेश भय्याजी जोशी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए जरूरी कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार को उन क्षेत्रों में शांति स्थापित करनी चाहिए जहां भी अशांति है।

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▸ पृष्ठ 3

चीन-जापान से लाए गए 236 भारतीय व विदेशी नागरिक

नई दिल्ली : कोरोना वायरस से प्रभावित चीन के वुहान व जापान के टोक्यो से गुरुवार को 195 भारतीयों समेत 236 लोगों को दिल्ली लाया गया। इन सभी को आइटीबीपी के कोरंटाइन शिविरों में 14 दिनों के लिए रखा गया है।

नेशनल न्यूज ▸ पृष्ठ 6

पुलवामा हमले की पूरी साजिश का पर्दाफाश जल्द : एनआइए

नई दिल्ली : पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले की पूरी साजिश से जल्द ही पर्दा उठ सकता है। एनआइए ने इस मामले में अहम सुबूत मिलने का दावा किया है। कई आरोपियों की पहचान हुई है और उनसे पूछताछ की जा रही है।

बिजनेस ▸ पृष्ठ 12

डाटा टैरिफ आठ गुना करना चाहती है वोडाफोन आइडिया

नई दिल्ली : एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू भुगतान को लेकर कारोबार बंद करने की आशंका जता चुकी वोडाफोन आइडिया ने सरकार के टैरिफ बढ़ाने की गुहार लगाई है। कंपनी का कहना है कि दरें बढ़ाकर ही वह बकाया चुकाने में सक्षम हो पाएगी।

अंतरराष्ट्रीय ▸ पृष्ठ 13

अब ब्रिटेन पहुंच रहे सबसे ज्यादा भारतीय छात्र

लंदन : भारतीय छात्रों के लिए ब्रिटेन बड़े शैक्षिक हब के रूप में उभर कर सामने आया है। चालू सत्र में पढ़ाई के लिए पहुंचने वाले विदेशी छात्रों में भारतीय छात्र सबसे ज्यादा हैं। यह तथ्य ब्रिटिश सरकार के गुरुवार को सार्वजनिक हुए आंकड़ों में सामने आया है।

विदेशी एजेंसियां दिल्ली हिंसा का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही हैं : भारत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- अमेरिका की यूएससीआइआरएफ और इस्लामिक देशों के संगठन ने दिल्ली मामले पर की टिप्पणी
- विदेश मंत्रालय ने कहा- वास्तविक स्थिति से वाकिफ नहीं हैं एजेंसियां, बातें झूठी और आधारहीन

रवीश कुमार फाइल फोटो

भारत ने इस्लामिक देशों के संगठन ओआइसी और अमेरिका में धार्मिक आजादी की निगरानी करने वाली एजेंसी यूएससीआइआरएफ समेत कुछ अमेरिकी सांसदों की तरफ से दिल्ली हिंसा के मुद्दे को उठाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। सरकार का कहना है कि इन्हें जमीनी स्थिति की जानकारी नहीं है और दिल्ली की स्थिति पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। सरकार मौजूदा माहौल के कूटनीतिक असर के आकलन में जुटी है। सारे कूटनीतिक चैनल खोल दिए गए हैं ताकि इसको लेकर भारत का पक्ष मजबूती से रखा जा सके।

गुरुवार को ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन (ओआइसी) और यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (यूएससीआइआरएफ) ने दिल्ली हिंसा पर लंबा बयान जारी किया। इसके अलावा अमेरिका में आगामी राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स के अलावा कई वरिष्ठ सीनेटरों ने भी तल्ख बयान दिए हैं। सैंडर्स ने सीधे तौर पर इस मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को घसीट लिया है जो एक दिन पहले ही भारत का दौरा खत्म कर स्वदेश लौटे हैं। जाहिर है कि सैंडर्स इस बहाने अपनी राजनीति साधना चाह रहे हैं। बहरहाल, यूएससीआइआरएफ ने सभी धर्म के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह भारत सरकार से किया है।

इस बारे में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, 'हमने यूएससीआइआरएफ, कुछ मीडिया और व्यक्तिगत स्तर पर दिल्ली में गत दिनों हुई हिंसा पर दी गई प्रतिक्रियाओं को देखा है। ये बातें झूठी व आधारहीन हैं। मामले का राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है।

रवीश कुमार ने कहा, कानूनी एजेंसियां हालात सामान्य करने की कोशिश में जुटी हैं। हालात काफी सामान्य हो चुके हैं। उच्च स्तर पर सरकार के प्रतिनिधियों ने स्थिति को सामान्य करने की अपील की है। पीएम मोदी ने भी शांति व भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया है। हम सभी से अपील करेंगे कि संवेदनहीन बयान नहीं दें।' कुमार ने सीधे तौर पर अमेरिकी नेता सैंडर्स का नाम नहीं लिया लेकिन बयान से साफ है कि उनकी तरफ भी इशारा किया गया है। विदेश मंत्रालय के अधिकारी बताते हैं कि दुनियाभर में विदेश मंत्रालय के अधिकारी अपने स्तर पर भारतीय पक्ष को रखने की भरसक कोशिश कर रहे हैं।

बंगाल में एक और स्टिंग ऑपरेशन से तृणमूल मुश्किल में

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

गर्म हुई सियासत

- छह मंत्रियों, दो विधायक समेत 12 लोगों के कथित तौर पर रिश्वत लेने का वीडियो आया सामने
- मुख्यमंत्री से वीडियो में नजर आ रहे लोगों को हटाने व मामले की सीबीआइ जांच कराने की मांग

बंगाल में चुनावी मौसम में एक और स्टिंग ऑपरेशन को लेकर सियासत गरम हो गई है। इस वीडियो फुटेज को भाजपा ने जारी किया है। इससे पहले 2016 के विधानसभा चुनाव के दौरान ही नारद स्टिंग कांड सामने आया था, जिसकी जांच अब तक सीबीआइ कर रही है। भाजपा इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला कर रही है क्योंकि इस स्टिंग कांड में भी बंगाल की सत्ता पर काबिज दल के नेता-मंत्री और विधायक शामिल हैं, जो एक वीडियो फुटेज में कथित रूप से रिश्वत लेते दिख रहे हैं। स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो में दिखने वाले मंत्रियों, विधायकों और नेताओं का कहना है कि भाजपा ने उन्हें फंसाने के लिए फर्जी वीडियो तैयार किया है। इस मामले में स्टिंग करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है।

भाजपा को मिला एक और मौका : अगले कुछ माह में बंगाल के शहरी निकायों में चुनाव होना है। उससे पहले इस तरह के वीडियो फुटेज के सामने आने से तृणमूल और खासकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चिंता बढ़ गई है। तृणमूल, जो अब तक नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर भाजपा पर हमलावर थी, इस स्टिंग ने भाजपा को तृणमूल के खिलाफ फ्रंट फुट पर आने का मौका दे दिया है।

निजी टीवी चैनल का है स्टिंग : भाजपा ने मीडिया को यह वीडियो फुटेज दिखाया है। भाजपा के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि एक निजी टीवी चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया है और इसका वीडियो एक पत्रकार ने अपने फेसबुक पेज पर अपलोड किया है। उनका कहना है कि इस वीडियो में तृणमूल के एक दर्जन से अधिक मंत्री, विधायक व नेता रिश्वत लेते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से वीडियो में रिश्वत लेते नजर आ रहे लोगों को हटाने और मामले की सीबीआइ जांच कराने की मांग की और ऐसा नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

अमित शाह भी उठा सकते हैं मुद्दा

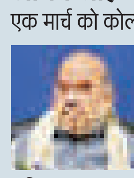

अमित शाह फाइल

एक मार्च को कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की सभा होनी है, उसमें इस मुद्दे पर शाह क्या कहते हैं, यह देखने वाली बात होगी। उस सभा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है भाजपा को तृणमूल कांग्रेस और ममता सरकार पर हमले का एक और मौका मिल गया है।

अमेरिका और तालिबान के बीच होने वाले समझौते में भारत होगा शामिल

- भारतीय नीति में बड़ा बदलाव, राजदूत पी. कुमारन करेंगे शिरकत

दोहा, प्रेट्र : अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौते के लिए मंच तैयार है। अफगानिस्तान में दो दशक से जारी हिंसा को रोकने के लिए शनिवार को खाड़ी देश कतर की राजधानी दोहा में समझौते पर दस्तखत होंगे। पाकिस्तान इस समझौते में प्रमुख पक्ष है। इसलिए प्रधानमंत्री इमरान खान गुरुवार को कतर पहुंच गए, लेकिन इस मंच पर भारत का अप्रत्याशित प्रवेश होने जा रहा है। कतर ने समझौता समारोह में भारत को आमंत्रित किया है और अब उसमें दोहा में मौजूद भारतीय राजदूत पी कुमारन शिरकत करेंगे। यह पहला मौका होगा जब भारत तालिबान को मान्यता देने वाले किसी आयोजन में शिरकत करेगा। माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई वार्ता के बाद यह नीतिगत बदलाव आया है। वैसे मॉस्को में 2018 में तालिबान की मौजूदगी वाली वार्ता में भारत ने अनौपचारिक शिरकत की थी।

कतर ने अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता को मान्यता दे रखी थी और दोहा में तालिबान का राजनीतिक कार्यालय काम कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के भारत दौरे में कहा था कि तालिबान के साथ होने वाले शांति समझौते को भारी समर्थन मिल रहा है। ट्रंप की यह टिप्पणी अफगानिस्तान में तालिबान की ओर से जारी हिंसा में कमी होने पर आई थी। अफगानिस्तान में दो दशक से जारी हिंसा में दसियों हजार लोग मारे जा चुके हैं और 25 लाख से ज्यादा विस्थापित होकर देश छोड़ चुके है। अफगानिस्तान बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। इस समझौते से 2001 से अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिका के 14 हजार सैनिकों की वापसी का रास्ता साफ होगा। 19 साल से जारी संघर्ष में अमेरिकी सेना अपने 2,400 सैनिकों की जान गंवा चुकी है। यह अमेरिका के लिए सबसे लंबा युद्ध साबित हुआ है जिसमें अमेरिका को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ट्रंप ने 2016 में चुनाव प्रचार के दौरान अमेरिका में वादा किया था कि राष्ट्रपति बनने पर वह अफगानिस्तान से सैनिकों को वापस बुलाएंगे। इससे जन और धन, दोनों का नुकसान बचेगा।

इमरान द्विपक्षीय हितों को भी साधने में जुटे : इमरान की दोहा में कतर के अमीर (सत्ता प्रमुख) शेख तमीम बिन हामद अल-थानी से मुलाकात हुई है। इमरान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने नेता की कतर के अमीर से मुलाकात का वीडियो जारी करते हुए ट्वीट से इसकी सूचना दी है। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश विभाग ने इमरान की कतर यात्रा के संबंध में कहा था कि इससे दोनों देशों के संबंध मजबूत होंगे और क्षेत्रीय विकास के लिए सहयोग बढ़ेगा। 2018 के बाद इमरान की प्रधानमंत्री के रूप में यह दूसरी कतर यात्रा है।

लार्सन एंड टूब्रो बना सकती है अयोध्या में भव्य राम मंदिर

माला दीक्षित, नई दिल्ली : अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण की तैयारियां जोरों पर हैं। वैसे तो मंदिर निर्माण के लिए कई कंपनियों के नामों की चर्चा हैं लेकिन लार्सन एंड टूब्रो (एलएंडटी) इनमें सबसे आगे है। कंपनी भव्य मंदिर निर्माण के लिए तकनीकी और निर्माण संबंधी पूरा सहयोग करने की इच्छा रखती है, लेकिन कंपनी निर्माण का कांट्रेक्ट यानी ठेका नहीं लेगी। कंपनी भगवान के मंदिर निर्माण का काम सेवाभाव से करना चाहती है। मंदिर विकास और प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्रा 29 फरवरी को अयोध्या जाएंगे और वहां भगवान के दर्शन करने के बाद शाम को बैठक होगी जिसमें मंदिर निर्माण और अन्य पहलुओं पर चर्चा होने की संभावना है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक बने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक दिल्ली मे 19 फरवरी को हुई थी। उसके बाद से मंदिर निर्माण के लिए तेजी से काम चल रहा है। इन सारी बातों पर विस्तृत चर्चा और फैसला ट्रस्ट की अगली बैठक में ही हो सकता है। अयोध्या में ट्रस्ट के कार्यालय के लिए भी स्थान ढूंढा जा रहा है। ट्रस्ट के कार्यालय के लिए सुंदर भवन पर भी विचार हो रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, रामलला को नवरात्र से पहले नये स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रयास होगा। हालांकि अभी इसकी तारीख तय नहीं है। भगवान के श्री विग्रह को स्थानांतरित करने में उनकी सुरक्षा और दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। भक्तों के दर्शन की वर्तमान दूरी को कम करने पर भी विचार चल रहा है। अभी रामलला के दर्शन 50 फीट दूर से होते हैं। रामलला की परिक्रमा पर भी विचार हो रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रस्ट का खाता खुलने की भी औपचारिकताएं चल रही हैं।

भूतल पर विराजेंगे रामलला, प्रथम तल पर सजेगा राम दरबार पेज>>7

शर्मनाक

पाकिस्तान की करतूतों से दुनिया वाकिफ है, आए दिन कोई न कोई देश या वैश्विक संगठन उसकी लानत मलानत करता है, इस बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार मामलों की प्रमुख ने पाक को बेपर्दा किया है

अल्पसंख्यक उत्पीड़न पर खुली पाक की कलई

- संरा मानवाधिकार प्रमुख ने कहा, पाक में धर्मस्थलों पर हो रहे हैं लगातार हमले
- विवादास्पद ईशनिंदा कानून नहीं बदल रही इमरान सरकार
- इस कानून में गवाहों के बयान पर ही आरोपित को मौत की सजा का है प्रावधान

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैचलेट। रायटर

जिनेवा, प्रेट्र : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भले ही अपने देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों को बराबरी से देखे जाने का दावा करें लेकिन संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट ने उनके दावे की कलई खोल दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यक हिंसा के शिकार हैं और उनके धर्मस्थलों पर हमले हो रहे हैं। सरकार उस ईशनिंदा कानून में बदलाव करने में विफल रही है जो अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का सबसे बदनाम कानून है। इस कानून में गवाहों के बयान पर ही मौत की सजा का प्रावधान है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार मामलों की प्रमुख मिशेल बैचलेट ने मानवाधिकार परिषद के सत्र में पाकिस्तानी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जुनैद हाफिज का मामला रखा। इस मामले में बीती दिसंबर में पाकिस्तानी अदालत ने ईशनिंदा मामले में उनके लिए मौत की सजा का एलान किया है। बैचलेट ने कहा, पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यक हिंसा के लगातार शिकार हो रहे हैं, उनके पूजास्थलों पर हमले किए जा रहे हैं। कानून भी उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बार-बार कहने के बावजूद पाकिस्तान हालात में सुधार नहीं कर रहा और न ही ईशनिंदा कानून में संशोधन कर रहा है। मिशेल अफ्रीकी देश चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं।

बुधवार को पाकिस्तान की मानवाधिकार मामलों की मंत्री शिरीन मजारी ने सत्र को संबोधित करते हुए कहा था कि उनकी सरकार बच्चों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून में बदलाव करने पर गंभीरता से विचार कर रही है और आगे बढ़ रही है।

इन्हीं अल्पसंख्यकों से संबंधित है भारत का सीएए : पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के हो रहे उत्पीड़न के मद्देनजर ही भारत में नागरिकता कानून में संशोधन (सीएए) किया गया है। पाकिस्तान समेत तीन पड़ोसी देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को अब महज छह साल के प्रवास पर ही भारत की नागरिकता मिल सकेगी। पहले 12 साल के प्रवास के बाद नागरिकता के लिए आवेदन देना होता था।

कोरेगांव भीमा के 348 केस वापस

मुंबई, प्रेट्र : महाराष्ट्र सरकार ने कोरेगांव भीमा से संबंधित 348 व मराठा आंदोलन से संबंधित 460 मामले वापस ले लिए हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने विधान परिषद में गुरुवार को एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। गृह मंत्री ने यह भी कहा, प्रस्तावित नानार रिफाइनरी परियोजना के विरोध में दर्ज पांच में से तीन मामले भी राज्य सरकार वापस ले चुकी है। बाद में देसाई ने पत्रकारों को बताया कि नियमानुसार ये मामले वापस लिए गए हैं।

देशमुख ने कहा, 'कोरेगांव भीमा हिंसा में दर्ज कुल 649 मामलों में से 348 और मराठा आरक्षण आंदोलन में दर्ज 548 में से 460 मामले अभी तक वापस लिए जा चुके हैं। शेष मामले जांच पूरी होने के बाद वापस लिए जाएंगे। ऐसे मामलों के वापस लिए जाने की प्रक्रिया चल रही है।' देशमुख ने यह भी कहा कि यलगार परिषद मामले की जांच के लिए राज्य सरकार महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत जांच आयोग बिठाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यलगार परिषद मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को (एनआइए) सौंपी गई है उससे वह हताश हैं। मंत्री ने कहा कि उन्हें कई ज्ञापन मिले हैं जिसमें शिकायत की गई है कि पूर्व के भाजपा शासन ने सरकार के खिलाफ बोलने वाले को 'अर्बन नक्सल' कह दिया था।

पुणे पुलिस के अनुसार, 31 दिसंबर 2017 को पुणे में यलगार परिषद सम्मेलन आयोजित किया गया था। नक्सल समर्थकों द्वारा इस सम्मेलन में भड़काऊ भाषण दिए गए जिससे अगले दिन जिले में कोरेगांव भीमा युद्ध स्मारक पर जातिवादी हिंसा भड़क उठी। केंद्र ने पिछले महीने यलगार परिषद मामले की जांच पुणे पुलिस से एनआइए को हस्तांतरित कर दी थी। इस कदम की शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस की महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार ने आलोचना की। हालांकि राज्य सरकार ने बाद में अपना रुख बदल लिया और कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांच अपने हाथों में लेने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है।